



दक्षिण भारत राष्ट्रमत

தக்ஷிண் பாரதத் ராஷ்ட்ரமத் | தினகரி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बेंगलूरु से एक साथ प्रकाशित



5 कुलदीप यादव करियर की सर्वश्रेष्ठ 14वीं टेस्ट रैंकिंग पर

6 गाजा में एक नई सुबह : युद्ध से शांति की ओर कदम

7 प्रेग्नेसी के दौरान की थी 'दे दे प्यार दे 2' की शूटिंग : इशिता दत्ता

GST बचत उत्सव

मेरे परिवार के लिए छुट्टियों पर बाहर घूमना हुआ सस्ता

GST राहत लाई खुशियों की सौगात

अब ₹5,000 प्रति दिन तक के होटल स्टे पर तीन दिन में ₹1,050 तक की बचत

फर्स्ट टेक

भारत सातवीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए निर्वाचित

न्यूयॉर्क/भाषा। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के 2026-28 के कार्यकाल के लिए चुना गया है और यह भारत का सातवां कार्यकाल होगा। यूएनएचआरसी ने मंगलवार को हुए चुनाव के नतीजों की घोषणा करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत का तीन वर्ष का कार्यकाल एक जनवरी, 2026 से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने समर्थन देने के लिए सभी प्रतिनिधिमंडलों का सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, भारत आज सातवीं बार 2026-28 के कार्यकाल के लिए मानवाधिकार परिषद के लिए चुना गया है। राजनयिक ने कहा कि यह चुनाव मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारत-यूरोपीय संघ ने किया आतंकवाद-विरोधी संयुक्त प्रशिक्षण

नई दिल्ली/भाषा। यूरोपीय संघ और भारत ने शत्रुतापूर्ण ड्रोन से उभरते खतरों के खिलाफ महत्वपूर्ण अवसरचना और आसान लेखों (सॉफ्ट टारगेट) की सुरक्षा के लिए अपनी तरह का पहला, आतंकवाद-विरोधी संयुक्त प्रशिक्षण आयोजित किया। गुलुगुलाम में बुधवार को समाप्त हुए इस तीन दिवसीय अभ्यास में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) और यूरोपीय संघ के 'हाई रिस्क सिस्व्यारिटी नेटवर्क' (एचआरएसएन) के वरिष्ठ अधिकारी, प्रशिक्षक और तकनीकी विशेषज्ञ एक साथ आए। यूरोपीय संघ के एक बयान में कहा गया है कि मानव रहित हवाई प्रणालियों (यूएसए) का तेजी से प्रसार और राज्य तथा गैर-राज्यीय तत्वों द्वारा उनका दुरुपयोग गंभीर सुरक्षा चुनौतियां पैदा करता है। बयान में कहा गया है कि वाणिज्यिक ड्रोनों ने प्रौद्योगिकी और पहुंच दोनों में तेजी से प्रगति की है, जिससे वे सस्ते और अनुकूल उपकरण बन गए हैं।

आध्यात्मिकता के बिना नैतिकता का कोई अर्थ नहीं : मोहन भागवत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

अहमदाबाद/भाषा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को कहा कि आध्यात्मिकता के बिना नैतिकता का कोई अर्थ नहीं है और अगर लोग यह मंत्र अपनाएं कि 'मैं सब में हूँ और सब मुझमें हूँ' तो समाज में हिंसा रुक जाएगी।

गुजरात दौरे के दूसरे दिन, भागवत गांधीनगर शहर के पास कोबा स्थित प्रेक्षा विश्व भारती ध्यान केंद्र गए और आध्यात्मिक गुरु आचार्य महाश्वमजी से मुलाकात की।

इस अवसर पर आरएसएस प्रमुख ने कहा, 'मैं हर साल इस जगह आता हूँ ताकि अपनी



ऊर्जा को पुनः संचारित कर सकूँ। संघ द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में भागवत के हवाले से कहा गया, व्यक्तिगत चरित्र और राष्ट्रीय चरित्र का आधार नैतिकता है और नैतिकता की नींव आध्यात्मिकता है, क्योंकि आध्यात्मिकता के बिना नैतिकता का कोई अर्थ नहीं है।

इसलिए मैं उन स्थानों पर जाता हूँ जहाँ मुझे अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। आचार्य महाश्वमजी की अहिंसा की शिक्षाओं का उल्लेख करते हुए, भागवत ने कहा, अगर लोग उनके इस मंत्र - 'मैं सब में हूँ और सब मुझमें हूँ' को अपनाए तो समाज में

हिंसा रुक जाएगी। भागवत ने कहा कि आरएसएस के चल रहे शताब्दी वर्ष में कोई बड़ा आयोजन नहीं किया जाएगा क्योंकि 'अगर हम देश के लिए काम करते हुए 100 साल पूरे करते हैं, तो यह हमारा कर्तव्य था, इसका जश्न मनाने की कोई जरूरत नहीं है।

भागवत ने कहा कि बड़े-बड़े समारोहों के बजाय, आरएसएस कार्यक्रमों में ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया है जो पूरे समाज में समरसता पैदा करें।

संघ प्रमुख ने कहा, हमने पांच प्रकार के कार्यक्रमों के बारे में सोचा है जिनमें पारिवारिक शिक्षा, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, नागरिक कर्तव्य और स्वदेशी पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

2027 में पहला मानवयुक्त अंतरिक्षयान जाएगा : नारायणन

■ मानवयुक्त चंद्र मिशन 2040 तक



रांची/भाषा। इसरो के अध्यक्ष सी. नारायणन ने बुधवार को कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी ने 2040 तक भारतीयों को चंद्रमा पर उतारने का लक्ष्य रखा है, जबकि उसकी पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन 'गगनयान' 2027 में प्रक्षेपित करने की तैयारी है।

नारायणन ने कहा कि वर्तमान में कई महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष परियोजनाएँ और क्षेत्रगत सुधार चल रहे हैं, जिनमें 2035 तक एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और 2026 तक तीन मानवरहित 'गगनयान' मिशन शामिल हैं। उनके अनुसार, इनमें से पहला मिशन अर्ध-मानव रोबोट 'व्योममित्र' को दिसंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। नारायणन ने 'पीटीआई-संगठन' (इसरो) प्रमुख ने कहा कि

भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (बीएसएस) के 2035 तक स्थापित होने की उम्मीद है, और अंतरिक्ष में प्रारंभिक मॉड्यूल 2027 की शुरुआत में स्थापित होने की उम्मीद है।

वह रांची स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बीआईटी) मेसरा के 35वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने आए थे।

नारायणन ने कहा, 'गगनयान' में कई विकास कार्य हो रहे हैं। हम कुछ और प्रयोगों की योजना बना रहे हैं। मानवयुक्त मिशन से पहले, हम तीन मानवरहित मिशनों की योजना बना रहे हैं। 'व्योममित्र' इस साल दिसंबर में उस पर उड़ान भरेगा। अगले साल दो और मानवरहित मिशन होंगे। मानवयुक्त 'गगनयान' मिशन 2027 की पहली तिमाही तक संभव होगा।

भारत रेल प्रौद्योगिकी प्रणालियों में विश्व का नेतृत्व करने की राह पर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com



नई दिल्ली/भाषा। रेल मंत्री अश्विनी बैण्ण ने बुधवार को कहा कि भारत रेल प्रौद्योगिकी प्रणालियों में दुनिया का नेतृत्व करने की राह पर है और इंजीनियरिंग नवाचार में सबसे आगे है। मंत्री ने यहां भारत मंडप में अंतरराष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी (आईआईईई) के 16वें संस्करण का उद्घाटन किया। रेल मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिषद (सीआईआई) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित आईआईईई-2025 में

नवाचार और निवेश के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है।

बैण्ण ने कहा, भारत रेल प्रौद्योगिकी प्रणालियों में विश्व का नेतृत्व करने की राह पर है और इंजीनियरिंग नवाचार में अग्रणी है। भारतीय और वैश्विक उपकरण निर्माताओं तथा संपूर्ण रेलवे पारिस्थितिकी तंत्र को एक मंच पर लाना एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने कहा, 2024-25 में 7,000 कोच, 42,000 वैगन और 1,681 इंजनों के रिकार्ड उत्पादन के साथ, भारतीय रेलवे एक विकसित राष्ट्र की ओर भारत की यात्रा को शक्ति प्रदान कर रहा है।

भगवान राम और कृष्ण से जुड़े स्थानों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करेगी मप्र सरकार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com



निवाड़ी (मप्र)/भाषा। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार श्री राम वन गमन पथ और भगवान कृष्ण से जुड़े स्थानों को तीर्थ स्थलों के रूप में विकसित करेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए पहले ही धन आवंटित कर दिया गया है। यादव ने कहा कि चित्रकूट और ओरछा में लगभग 2,200 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कार्य जारी है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि अभी तक प्रदेश के 11 जिलों के 25 स्थलों को 'राम वन गमन पथ' से जोड़ा गया है। ये वे स्थान हैं जहां वनवास के समय भगवान श्रीराम गए थे। इनमें सतना में चित्रकूट सहित कई स्थल पहले से श्रीराम के प्रवास के लिए जाने जाते हैं। कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां माना जाता है भगवान राम आए थे या रुके थे पर वे प्रसिद्ध नहीं हैं यानी कम ज्ञात हैं।

यादव ने कहा, 'श्री राम वन गमन पथ और भगवान कृष्ण से जुड़े जगहों को तीर्थ स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार ने फंड को मंजूरी दे दी है।' उन्होंने निवाड़ी जिले के ओरछा में श्री राम

राजा लोक के दूसरे चरण और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए भूमि पूजन समारोह को संबोधित करते हुए ये घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा, 'भगवान श्री राम का नाम ही काफी है। उनका नाम और गुण महान हैं। अपने गुणों, आचरण, अपने पिता के प्रति समर्पण और अपनी प्रजा की देखभाल के माध्यम से, राम सबसे सदाचारी भगवान श्री राम बने।'

इससे पहले मुख्यमंत्री ने ओरछा में श्रीराम राजा सरकार मंदिर के प्रांगण में पूजा-अर्चना की। उन्होंने ओरछा में मुख्य मंदिर के चारों ओर भगवान राम के चरणों की निरीक्षण किया।

यादव ने घोषणा की कि निवाड़ी शहर को नगर परिषद का दर्जा देने के लिए समीक्षा की जाएगी।

16-10-2025 सुबह 5:49 बजे 17-10-2025 सुबह 5:59 बजे

BSE 82,605.43 (+575.45) NSE 25,323.55 (+178.05)

सोना 12,783 रु. (24 कैरेट) प्रति ग्राम चांदी 177,000 रु. प्रति किलो

मिशन मंडेला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com



कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

घातक क्षेत्रवाद

कुछ खुदमजूरों के भय से, ना करें पलायन रखें याद। सारा भारत है घर अपना, है निंदनीय ऐसा विवाद। सड़ जाएगा सम्पूर्ण राष्ट्र, यह फैला यह गया भवाद। सख्ती से निपटो तत्वों से। घातक होता है क्षेत्रवाद।

कर्नाटक सरकार ने कर्मचारियों, पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाया

बेंगलूरु/भाषा। कर्नाटक सरकार ने बुधवार को दीपावली से पहले अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को उनके मूल वेतन के 12.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 14.25 प्रतिशत करने का आदेश जारी किया। वित्त विभाग ने बताया कि यह बड़ोत्तरी पेंशनधारकों पर भी लागू होगा। आदेश के अनुसार, संशोधित महंगाई भत्ता एक जुलाई से प्रभावी होगा। चालू वित्त वर्ष में यह दूसरी बार है, जब महंगाई भत्ते में वृद्धि की गयी है। इससे पहले मई में, सरकार ने महंगाई भत्ते को मूल वेतन के 10.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.25 प्रतिशत कर दिया था।

बीएसएनएल ने नए ग्राहकों के लिए सिर्फ एक रुपये में 4जी सेवा की पेशकश की

नई दिल्ली/भाषा। सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल ने बुधवार को दिवाली के अवसर पर नए ग्राहकों के लिए केवल एक रुपये में एक महीने तक 4जी सेवा देने वाली खास पेशकश की। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने बयान में कहा कि इस पेशकश के तहत नए ग्राहकों को 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, 2025 तक 4जी सेवा मुहैया कराई जाएगी। दूरसंचार कंपनी ने कहा, बीएसएनएल ने दिवाली मनाने के लिए नए ग्राहकों को केवल एक रुपये के शुल्क पर 4जी मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने का फैसला किया है। यह पेशकश एक महीने तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के मान्य रहेगी। इस योजना के तहत नए ग्राहकों को अनलिमिटेड वॉयस कॉल, रोजाना 2 जीबी हाई-स्पीड डेटा, प्रतिदिन 100 एसएमएस और एक मुफ्त सिम कार्ड मिलेगा।

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ 48 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की

इस्लामाबाद/भाषा। पाकिस्तान ने बुधवार को कहा कि अफगानिस्तान के साथ 48 घंटे के संघर्ष विराम पर सहमति बन गई है। यह घोषणा ऐसे समय की गई है जब दोनों देशों के बीच सीमा पर संघर्ष में दोनों ओर से कई लोग मारे गए हैं। 'डॉन' अखबार ने विदेश कार्यालय के हवाले से कहा है, तालिबान के अनुरोध पर दोनों पक्षों की आपसी सहमति से आज शाम छह बजे से अगले 48 घंटों के लिए पाकिस्तान सरकार और अफगान तालिबान शासन के बीच एक अस्थायी संघर्ष विराम का फैसला किया गया है। विदेश कार्यालय ने कहा, इस अवधि के दौरान, दोनों पक्ष रचनात्मक बातचीत के माध्यम से इस जटिल लेकिन सुलझने योग्य मुद्दे का सकारात्मक समाधान खोजने के लिए गंभीर प्रयास करेंगे। अफगानिस्तान सरकार की ओर से फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं आई है।

हिंदुओं की उदारता, शक्ति का नहीं होना चाहिए इस्लामीकरण : उमा भारती

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मैहर (मध्यप्रदेश)/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने बुधवार को कहा कि हिंदू धर्म में उदारता और सामाजिकता का भाव है तथा हिंदुओं की इस उदारता एवं उनकी शक्ति का इस्लामीकरण नहीं होना चाहिए।

मैहर स्थित मां शारदा पीठ में पूजा-अर्चना के बाद हिंदू मंदिरों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश को लेकर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भारती ने यह बात कही। उन्होंने कहा, 'गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध केवल जगन्नाथपुरी मंदिर में लागू है। हमारे धर्म में उदारता और सामाजिकता का भाव है। हिंदुओं की उदारता और हमारा बल साथ बना रहे। हमें हिंदू धर्म का इस्लामीकरण नहीं करना चाहिए।'

उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म सबसे अच्छी विचारधारा वाला धर्म है, लेकिन इसकी सहजता को कमजोरी समझना गलत है। उन्होंने कहा, 'हमारे धर्म की उदारता और शक्ति

■ हिंदू धर्म सबसे अच्छी विचारधारा वाला धर्म है, लेकिन इसकी सहजता को कमजोरी समझना गलत है।

■ उमा भारती ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि गौ वंश के बारे में बोलने का उसे कोई अधिकार ही नहीं है।



दोनों ही हमारी पहचान हैं। हमें इन्हें किसी के प्रभाव में आकर नहीं बदलना चाहिए।'

एक अन्य सवाल के जवाब में उमा भारती ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि गौ वंश के बारे में बोलने का उसे कोई अधिकार ही नहीं है। उन्होंने कहा, 'कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा सनातन संस्कृति

और धार्मिक परंपराओं को कमजोर करने का काम किया है। कांग्रेस की विचारधारा गौवंश के विरोध में रही है। उनके शासन में देशभर में गौहत्या को बढ़ावा मिला।' उन्होंने कहा कि कांग्रेस यह पार्टी है, जिसने 1966 में गौ संरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे 400 से अधिक साधुओं पर गोली चलावाई थी।

कांग्रेस ने पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि उसके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने गौ मांस पर जीएसटी शून्य प्रतिशत कर दिया है, जिससे यह साफ होता है कि वह गौ हत्या और गौ मांस के निर्यात को बढ़ावा दे रही है।

चीन ने ईवी, बैटरी सब्सिडी पर डब्ल्यूटीओ में भारत की शिकायत की

नई दिल्ली/भाषा। चीन ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और बैटरी पर दी जा रही सब्सिडी को लेकर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में शिकायत दर्ज करवाई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बुधवार को कहा कि मंत्रालय डब्ल्यूटीओ के समक्ष चीन द्वारा रखी गई विरुद्ध प्रस्तावित गलियारे, भी राम राजा लोक के पहले चरण में स्वीकृत कार्यों का भी निरीक्षण किया। यादव ने घोषणा की कि निवाड़ी शहर को नगर परिषद का दर्जा देने के लिए समीक्षा की जाएगी।



जोधपुर प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का किया निरीक्षण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। शिक्षा एवं पंचायती राज एवं जोधपुर के जिला प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने बुधवार को जोधपुर जिला स्थित क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का निरीक्षण किया। उन्होंने जैसलमेर बस दुर्घटना में लापता अथवा पहचान के लिए प्रस्तुत किए गए मृतकों के डीएनए सैम्पलों के परीक्षण कार्य की स्थिति की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान मंत्री दिलावर ने प्रयोगशाला के डीएनए अनुभाग का भ्रमण किया तथा उपस्थित वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों से परीक्षण की

सम्पूर्ण प्रक्रिया, सैम्पल रिसीविंग से लेकर प्रोफाइल जेनरेशन तक के प्रत्येक चरण की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने सैम्पलों की प्राथमिक स्क्रीनिंग, आइसोलेशन, एम्प्लीफिकेशन तथा डाटा विश्लेषण की प्रणाली का जायजा लिया और परीक्षण प्रक्रिया को समयबद्ध एवं वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप पूर्ण करने के निर्देश दिए।

प्रभारी मंत्री दिलावर ने कहा कि यह घटना अत्यंत दुःख है और राज्य सरकार प्रत्येक प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि डीएनए परीक्षण रिपोर्टों को शीघ्रतम समय में पूर्ण कर जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया जाए, ताकि मृतकों की पहचान कर उनके परिजनों को

यथाशीघ्र आवश्यक सहयोग और राहत प्रदान की जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि फोरेंसिक जांच की सटीकता और पारदर्शिता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा प्रत्येक सैम्पल की सुरक्षा, रिकॉर्ड-कीपिंग और टेस्टिंग लॉस को मानवीय संवेदनाओं के साथ तकनीकी दक्षता का संतुलन बनाए रखते हुए कार्य करें। निरीक्षण के दौरान युवा मामले एवं खेल विभाग राज्यमंत्री केके विशोई, जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी, प्रभारी सचिव जोधपुर दिनेश कुमार, जिला कलक्टर गौरव अग्रवाल, एफएसएल निदेशक अजय शर्मा सहित वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, डीएनए डिवीजन के विशेषज्ञ तथा जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे।

जानकारी प्राप्त की। प्रभारी मंत्री दिलावर ने कहा कि ऐसी आपात परिस्थितियों में प्रयोगशाला का कार्य राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने वैज्ञानिकों को प्रेरित करते हुए कहा कि मानवीय संवेदनाओं के साथ तकनीकी दक्षता का संतुलन बनाए रखते हुए कार्य करें। निरीक्षण के दौरान युवा मामले एवं खेल विभाग राज्यमंत्री केके विशोई, जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी, प्रभारी सचिव जोधपुर दिनेश कुमार, जिला कलक्टर गौरव अग्रवाल, एफएसएल निदेशक अजय शर्मा सहित वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, डीएनए डिवीजन के विशेषज्ञ तथा जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे।

पटवारी 45 हजार रुपये रिश्तत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार

जयपुर। राजस्थान के कोटा में बुधवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने एक पटवारी को 45 हजार रुपये रिश्तत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कोटा जिले में पटवार हल्का कैथुदा के पटवारी प्रधान चौधरी को रिश्तत मामले में गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि उसके एवं उसके परिजनों के नाम दर्ज कृषि भूमि की पैमाइश करवाने के लिए उसने उप तहसील कार्यालय खातौली में एक अर्जी दी थी जिसे कई दिन तक लंबित रखकर पटवारी प्रधान चौधरी 50,000 रुपये रिश्तत मांग रहा है। अधिकारियों के अनुसार जांच में पता चला कि प्रधान चौधरी भूमि की पैमाइश करने के लिए 50,000 रुपये में 5,000 रुपये ले चुका है। टीम ने आज जाल बिछाया तथा आरोपी पटवारी को 45 हजार रुपये रिश्तत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एक अन्य मामले में एसीबी टीम ने जयपुर में आयकर विभाग में एमटीएस के रूप में कार्यरत विष्णु पारीक को कथित रूप से 10,000 रुपये रिश्तत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।



गहलोत ने महागठबंधन के घटक दलों में सीट का बंटवारा जल्द होने की उम्मीद जताई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को उम्मीद जताई कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी महागठबंधन के घटक दलों में सीट के बंटवारे को लेकर जल्द ही फैसला हो जाएगा। गहलोत ने इस बारे में पूछे जाने पर यहां मीडिया से कहा, मेरे ख्याल से आजकल में निर्णय हो जाएगा। चर्चा चल रही है और मैं समझता हूं कि जल्द ही फैसला हो जाएगा। दिल्ली की एक अदालत में कथित

आईआरसीटीसी घोटाला मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद के खिलाफ आरोप तय किए जाने पर कटाक्ष करते हुए गहलोत ने कहा कि देश देख रहा है और समय आने पर माकूल जवाब देगा। कांग्रेस नेता ने कहा, यही तो आश्चर्य है, चुनाव के पहले अदालत भी सक्रिय हो जाती है, चुनाव के पहले ही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रयतन निदेशालय (ईडी) की सक्रियता दिखती है। इनको सोचना चाहिए कि चुनाव चल रहा है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कहते हैं सब को समान अवसर मिलने चाहिए तभी तो ये 'आचार संहिता' लागू होती है।

सत्ता पक्ष हो या विपक्ष ... सबको समान रूप से मैदान में उतरने का अवसर मिले, इसके लिए ही आचार संहिता लागू होती है। उन्होंने कहा कि अगर एक महीना बाद सीबीआई अदालत में चालान पेश करती तो क्या फर्क पड़ता? या चुनाव से चार महीना पहले ही ऐसा कर देते। उन्होंने कहा कि चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है और बुना के आप चालान पेश कर रहे हो, इसे क्या कहेंगे? उन्होंने कहा, देश देख रहा है, (समय) आने पर माकूल जवाब देगा। सत्ता में बैठे इन सब लोगों को ... राजग सरकार को सबक सिखाएगा।



मदन दिलावर महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती घायलों से मिले, जानी कुशलक्षेम कहा- यह त्रासदी अत्यंत पीड़ादायक, सरकार हर घड़ी प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। जिले के प्रभारी मंत्री मदन दिलावर बुधवार को जैसलमेर बस दुर्घातिका में घायल हुए यात्रियों से मिलने महात्मा गांधी अस्पताल के बर्न यूनिट पहुंचे। महात्मा गांधी अस्पताल के बर्न यूनिट में भर्ती घायलों की कुशलक्षेम पूछते हुए उन्होंने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। परिजनों से बातचीत के दौरान दिलावर ने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि यह समय पूरे प्रदेश को एक सूत्र में बांधने का है। राज्य सरकार इस दुःख की घड़ी में प्रत्येक प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार का हर विभाग राहत और सहयोग के कार्यों में सक्रिय है तथा पीड़ितों को हरसंभव सहायता दी जा रही है। उन्होंने दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से शोकाकुल परिवारों को यह असहनीय दुःख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। दिलावर ने अस्पताल

प्रशासन को निर्देश दिए कि सभी घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सीय उपचार और आवश्यक संसाधन तत्काल उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने चिकित्सकों से मरीजों की स्थिति, जलन के प्रतिशत, उपचार पद्धति और उपलब्ध संसाधनों की विस्तृत जानकारी ली। प्रभारी मंत्री ने सेंटिटेलर, ऑक्सीजन सपोर्ट, इंटेन्सिव केयर बेड्स, दवाइयों और नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता की समीक्षा की और निर्देश दिया कि प्रत्येक मरीज के लिए अलग चिकित्सीय निगरानी दल 24 घंटे मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। उन्होंने अस्पताल परिसर में डीएनए सैम्पल के लिए आए परिजनों से भी संवाद किया और उनके दहशने, भोजन एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की जानकारी ली। परिजनों ने प्रशासन द्वारा की गई त्वरित व्यवस्थाओं और संवेदनशील सहयोग के लिए आभार जताया। इस अवसर पर उद्योग राज्यमंत्री के.के. विशोई, विधायक जैसलमेर छोटी सिंह राठौड़ सहित अन्य जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में एसोसिएट प्रोफेसर के ठिकानों की तलाशी ली जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक आय अर्जित करने के कथित मामले में इन्दिरा गांधी पंचायती राज विकास संस्थान, जयपुर में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत एक अधिशासी अभियंता से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की है। ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी अधिकारी रामावतार मीणा द्वारा राजकीय सेवा में नियुक्त होने से अब तक करीब 2.77 करोड़ रुपये की आय से अधिक परिसम्पत्तियां अर्जित करने का खुलासा हुआ जो कि आरोपी की वैध आय से करीब 115 प्रतिशत अधिक है। गुप्त सूचनाओं और सत्यापन के आधार पर ब्यूरो ने पाया कि मीणा ने कथित तौर पर इंदिरा गांधी नगर जयपुर में लाखों रुपये मूल्य के छह बड़े भूखंड और मकान खरीदे।

जैसलमेर हादसे पर गजेन्द्र सिंह शेखावत ने जताया गहरा दुःख, बोले- पूरे प्रदेश को झकझोर देने वाली घटना

उदयपुर । जैसलमेर-जोधपुर के बीच रविवार को बस में आग लगने की भीषण दुर्घटना पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। शेखावत ने कहा कि यह पूरे प्रदेश को झकझोर देने वाली घटना है। बुधवार को उदयपुर में मीडिया से बातचीत में शेखावत ने बताया कि हादसे में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों में से 16 लोगों को जोधपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। उन्होंने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिया था। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे की जानकारी मिलते ही संवेदना व्यक्त की और प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। शेखावत ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मंगलवार को ही जोधपुर और जैसलमेर पहुंचे। उन्होंने घायलों से मुलाकात की और अस्पताल प्रशासन को सभी आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

विकसित राजस्थान 2047 विजन डायग्राम

भजनलाल शर्मा के विकसित राजस्थान के विजन को साकार करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के दूरदर्शी विकास की संकल्पना को समर्पित इस विजन डॉक्यूमेंट की कार्य योजना तैयार करने के साथ ही प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य की ओर बड़ा कदम बढ़ाया है। गरीब, युवा, महिला और किसानों के सशक्तिकरण को केन्द्र में रखते हुए यह दस्तावेज समावेशी विकास की भावना को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।



समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्रदेश के नागरिकों की आकांक्षाओं के अनुरूप तैयार किया गया है। इसके अन्तर्गत विस्तृत कार्य योजना के माध्यम से प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल प्रबंधन, शहरी विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में विकास के लिए लक्ष्य तय किये गए हैं। इनके अनुरूप प्रदेश में शत-प्रतिशत साक्षरता, कोशल आधारित शिक्षा, सुलभ एवं आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, जलवायु अनुकूल-जल प्रबंधन, स्मार्ट शहरीकरण और किफायती आवास सुनिश्चित किए जाएंगे। साथ ही, महिलाओं और युवाओं को कोशल, उद्यमिता एवं नेतृत्व के अवसर प्रदान कर उनकी

राज्य के विकास यात्रा में भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। यह विजन चार प्रमुख थीम और 13 सेक्टर पर आधारित है। पहली थीम जनकल्याण और सामाजिक सशक्तिकरण है, जिसमें कृषि-खाद्य प्रणाली, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक समावेशन जैसे आयाम शामिल हैं। दूसरी थीम त्वरित विकास, समृद्धि और रोजगार सृजन पर केंद्रित है, जिसके अंतर्गत औद्योगिक, खनन और पर्यटन क्षेत्रों में नई संभावनाएं विकसित की जा रही हैं। तीसरी थीम भविष्य उन्मुख राजस्थान की है, जिसमें आधारभूत अवसंरचना, जल सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थायिता और जलवायु अनुकूलता को प्राथमिकता दी गई है। राज्य सरकार ने वर्ष 2047

तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस विजन डॉक्यूमेंट में वर्ष 2047 तक कृषि क्षेत्र में जलवायु अनुकूल और तकनीक आधारित खेती के माध्यम से उत्पादकता में 40 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। हर नागरिक को स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में लाने, मातृ मृत्यु दर को 15 तक लाने, शिशु मृत्यु दर को प्रति हजार जीवित जन्मों पर 10 से कम करने और जीवन प्रत्याशा को 77 वर्ष तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है। विजन डॉक्यूमेंट अनुसार औद्योगिक विकास के माध्यम से राज्य में एक करोड़ से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।

दरवाजा जाम होने के कारण ज्यादा लोगों की जान गई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जैसलमेर/जोधपुर। जैसलमेर बस हादसे में बस का दरवाजा जाम होने के कारण उसमें सवार ज्यादा लोगों की जान गई। पुलिस ने बुधवार को बताया कि आग लगने के बाद इस एसी स्लीपर बस का दरवाजा जाम हो गया और यात्री बाहर नहीं निकल पाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बचाव और चिकित्सा सहायता की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा की और इस घटना को अत्यंत दुःख बताया। जलेश्वरीय है कि मंगलवार को दोपहर में जोधपुर जा रही एक निजी बस में जैसलमेर से रवाना होने के बमुश्किल दस मिनट बाद आग लग गई। देखते ही देखते बस आग का गोला बन गई और 20 यात्री जंदा जल गए और 15 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जैसलमेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश दान ने कहा कि आग लगने के कारण बस का गेट यानी

दरवाजा बंद हो गया, जिससे यात्री बाहर नहीं निकल सके। उन्होंने पीटीआई भाषा को बताया, ज्यादातर शव बस के गैलरी में मिले, जिससे पता चलता है कि लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम होने के कारण वे बाहर नहीं निकल पाए और असमय ही काल कवलित हो गए। इस बस में आग सेना के युद्ध स्मारक के पास लगी। वहां मौजूदा सेना के जवान तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव अभियान में शामिल हो गए। स्थानीय लोग व राहगीर भी मदद के लिए आगे आए। पास से गुजर रहे एक टैंकर से भी बस की आग बुझाने का प्रयास किया गया। बस दरवाजा जोर लगाकर तोड़ना पड़ा। आग लगने के बाद कुछ यात्री बस की खिड़की तोड़कर बाहर कूदे और अपनी जान बचाई। जैसलमेर के जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने बताया कि बस से 19 जले हुए शव बरामद किए गए और 16 गंभीर रूप से घायलों को जोधपुर के अस्पताल ले जाया गया।



इनमें से एक की बीच रास्ते में मौत हो गई। उन्होंने कहा, शवों को डीएनए सैंपलिंग और पहचान के लिए जोधपुर भेजा गया है। फोरेंसिक साइंस लैबोरेट्री (एफएसएल) द्वारा मिलान की पुष्टि के बाद उन्हें परिवारों को सौंप दिया जाएगा। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि बस में कुल कितने लोग थे इसकी पुष्टि की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश

दान ने कहा, 20 लोगों की मौत हो गई है और 15 का इलाज चल रहा है। अभी तक किसी के लापता की सूचना नहीं मिली है। हम लोगों की संख्या की पुष्टि कर रहे हैं। बस के रवाना होने के स्थान से लेकर रास्ते से सीसीटीवी फुटेज एकाग्र कर लिए गए हैं और उनकी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि एफएसएल की टीम कल रात से ही घटनास्थल का

निरीक्षण कर रही हैं। उन्होंने कहा, शुरुआती संकेत बस में शॉर्ट सर्किट की ओर इशारा कर रहे हैं, हालांकि बस में पटराखे होने जैसी अन्य आशंकाओं की भी जांच की जा रही है। जैसे ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मंगलवार शाम इस घटना की जानकारी मिली, उन्होंने जयपुर में अपनी निर्धारित बैठक बीच में ही समाप्त कर दी और मौके पर मौजूद अधिकारियों के साथ संपर्क करना शुरू कर दिया। अधिकारियों के अनुसार, बैठक में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, गौतम देव और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री शर्मा ने सभी को सुनिश्चित किया कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, वे जैसलमेर जा रहे हैं। एक अधिकारी ने कहा, मुख्यमंत्री ने घायलों को जैसलमेर से जोधपुर तक उन्नत उपचार के लिए सुचारु रूप से पहुंचाने के लिए अधिकारियों को एक ग्रीन कॉरिडोर बनाने का निर्देश दिया। वह रात में जैसलमेर पहुंचे और घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने बचाव और राहत

कार्यों में भारतीय सेना और स्थानीय नागरिकों के प्रयासों की सराहना की। इसके बाद मुख्यमंत्री जोधपुर गए और पीड़ितों के परिवारों से मिले। उन्होंने डॉक्टरों को घायलों को सर्वोत्तम संभव चिकित्सा सेवा प्रदान करने के निर्देश दिए और 'बर्न यूनिट' में चिकित्सा सुविधाओं की समीक्षा की। जोधपुर में इस हादसे में घायल हुए लोगों की चौबीसों घंटे देखभाल सुनिश्चित करने के लिए समर्पित चिकित्सा निगरानी दल तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री शर्मा ने यह भी निर्देश दिया कि घायलों के परिवारों को अस्पताल परिसर में उचित आवास, भोजन और सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाए। उन्होंने जैसलमेर और जोधपुर में स्थानीय विधायकों, पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रशासनिक अधिकारियों से बात की और उनसे राहत कार्यों में मदद करने की अपील की। उन्होंने कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर को भी स्थिति की निगरानी के लिए जोधपुर में रहने का निर्देश दिया। बचाव

अधिकारियों ने कहा हादसे का शिकार हुई बस देखते ही देखते आग का गोला बन गई और उसमें सवार लोगों को बचाव के लिए कुछ करने का ज्यादा समय नहीं मिला। हादसे का शिकार बस नई थी। उसका हाल ही में पंजीयन हुआ था और वह अपनी चौथी यात्रा पर निकली थी। यह दोपहर बाद लगभग तीन बजे जैसलमेर से रवाना हुई थी और रास्ते में और यात्रियों को लेने वाली थी। एक पुलिसकर्मी ने प्रत्यक्षदर्शी के हवाले से कहा कि बस के पिछले हिस्से से तेजी धमाका सुना गया जो संभवतः एल्टी कंफ्रेसर से हुआ था। डीजल, एसी गैस और फ्राइबर-आधारित अंदरूनी हिस्सों के कारण लगी आग और भड़क गई। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवासर ने कहा, बस में सिर्फ एक दरवाजा था, जो जाम हो गया था। ज्यादातर यात्री बाहर नहीं निकल पाए। सेना ने जितने संभव थे, शव निकाले। कुछ शव इतने जल गए थे कि उनकी पहचान करना मुश्किल है।

प्रभावित करती है। बौद्धिक शिक्षा के साथ उच्च शैक्षणिक रिकॉर्डों वाला व्यक्ति और मूल्य आधारित शिक्षा में विवाल्या हो तो समाज के किसी काम का नहीं है। गीआईटी मेसरा के 35वें वीक्षांत समारोह में 1,000 स्नातक छात्रों, 320 स्नातकोत्तर छात्रों, 75 पीएचडी छात्रों और 65 डिप्लोमा धारकों को उपाधियाँ प्रदान की गईं। इसके अतिरिक्त, उक्तूष प्रशंसन करने वाले छात्रों को निरंतर शैक्षणिक उक्तूषता के लिए स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। बीआईटी मेसरा के चांसलर सीके बिडला ने कहा, वीक्षांत समारोह न केवल एक शैक्षणिक यात्रा का समापन है, बल्कि जिज्ञासा और नवाचार की आजीवन खोज की शुरुआत भी है। आज दुनिया ऐसे नेताओं की मांग कर रही है जो स्वरुता से सोच सकें और उद्देश्यपूर्ण निर्माण कर सकें।

सुविचार

चिकित्सा का उद्देश्य बीमारी को रोकना और जीवन को लम्बा करना है; चिकित्सक की आवश्यकता को समाप्त करना ही औषधि का आदर्श है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

नक्सलवाद का खिसकता आधार

नक्सलवाद का खिसकता आधार केंद्र सरकार और सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता को दर्शाता है। हाल के वर्षों में कई नक्सलियों का खात्मा हुआ है। वहीं, हथियार छोड़कर मुख्यधारा में आने वाले नक्सलियों की संख्या भी बढ़ी है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भाकपा (माओवादी) के 88 सदस्यों के आत्मसमर्पण से पता चलता है कि एक ओर जहां नक्सलविरोधी अभियान अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं, वहीं गुमराह होकर ऐसे संगठनों में शामिल होने वाले लोगों को भी हकीकत मालूम हो रही है। कथित क्रांति और इन्साफ के नाम पर नागरिकों को उलटी पट्टी पढ़ाने का यह खेल अब ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। जो लोग बहकावे में आकर अपने ही देश के खिलाफ बंदूक उठा लेते हैं, वे या तो सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मारे जाते हैं या जंगलों में मारे-मारे फिरते हैं। इससे समाज का कौनसा भला हो जाएगा? क्या तोड़फोड़, आगजनी, हिंसा, उपद्रव करने से नागरिकों का भविष्य उज्ज्वल हो जाएगा? हाल में कुछ नक्सलियों ने झारखंड के प. सिंहभूम जिले में एक दूरसंचार कंपनी के मोबाइल टावर को आग लगा दी थी। देर रात नक्सलियों का एक समूह आया, जिसने पहले तो कंपनी के कर्मचारियों को वहां से भागया, उसके बाद टावर को आग के हवाले कर दिया। इससे किसका नुकसान हुआ? कंपनी की सेवाएं लेने वालों में ज्यादातर आम आदमी हैं। नेटवर्क न मिलने से उनके कामकाज बाधित हुए। ये नक्सली स्थानीय लोगों को नुकसान पहुंचाकर किस इन्साफ की बात करते हैं? अगर लोगों के जीवन एवं अधिकारों की इतनी ही परवाह है तो ऐसा माहौल बनाना चाहिए, जिससे वह अच्छे स्कूल और अस्पताल खुलें। लोगों के पास रोजगार हो। उनका जीवन आसान हो। तेल छिड़ककर आग लगाने और लोगों का जीवन मुश्किल बनाने में कौनसी महानता है?

जो नक्सली अपने जीवन के कई साल इन संगठनों में बर्बाद कर चुके हैं, उनसे बेहतर इनकी हकीकत और कौन जानता होगा! वे धीरे-धीरे समझ रहे हैं कि इसका नतीजा सिर्फ तबाही है, इसलिए अब तौबा करते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले में मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस के सामने पांच दर्जन से ज्यादा नक्सलियों का आत्मसमर्पण इसकी एक मिसाल है। इनमें एक ऐसा व्यक्ति भी था, जो युवावस्था में इस विचारधारा से प्रभावित होकर नक्सली बन गया था। वह 50 साल से ज्यादा अवधि तक नक्सली गतिविधियों में सक्रिय रहा। अब 69 साल की उम्र में उसका इन सबसे मोहभंग हो गया। जो व्यक्ति किसी हिंसक विचारधारा का खोखलापन महसूस कर लेता है, उसके मन में कहीं-न-कहीं उससे दूर जाने का विचार जरूर पैदा होता है। जो लोग मुख्यधारा में आना चाहते हैं, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। कहते भी हैं कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हां, उसके बाद यह दृढ़ संकल्प लेना जरूरी है कि दोबारा कोई भूल न हो, किसी के बहकावे में न आए। इन लोगों को स्वरोजगार का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। स्थानीय लोगों को नसीहत दी जाए कि इनके साथ अच्छा बर्ताव करें और आगे बढ़ने में सहयोग करें। प्रायः हर जगह कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, जो दूसरों के निजी जीवन के बारे में जानकारी हासिल करने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। वे ‘तिल का ताड़’ बनाते देर नहीं लगाते। वे अपनी टीका-टिप्पणियों से किसी को आहत न करें। इसके अलावा इनकी सुरक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए। नक्सली संगठन उन लोगों से बहुत घृणा करते हैं, जो छोड़कर चले जाते हैं। इनमें भर्ती होना (तुलनात्मक रूप से) आसान है, लेकिन इनसे पीछा छुड़ाकर जाना आसान नहीं है। स्थानीय पुलिस को भी इन लोगों की हर संभव मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। सर्वसमाज के योगदान से ही नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है।

ट्वीटर टॉक

गोवा सरकार में कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री रवि नाइक के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को अपने परमधाम में स्थान दें एवं शोकाकुल परिजनों को यह वज्रपात सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

–भजनलाल शर्मा

ग्रामीण महिलाएं हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूत आधारशिला हैं। वे केवल परिवार की नहीं, बल्कि राष्ट्र की प्रगति की वास्तविक प्रेरक शक्ति हैं। एक सशक्त, शिक्षित और आत्मनिर्भर ग्रामीण मातृशक्ति ही सभ्य समाज और समृद्ध भारत का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

–वसुंधरा राजे

महान वैज्ञानिक, मिसाइल मैन, ‘भारत रत्न’ डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम जी की जयंती पर उन्हें कोटिशः नमन करता हूँ। भारतीय अंतरिक्ष एवं रक्षा अनुसंधान को नई दिशा प्रदान करने वाले डॉ. कलाम का जीवन सादगी, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण रहा।

–जेपी नड्डा

प्रेरक प्रसंग

अंतहीन भक्ति

एक बार श्रीकृष्ण अर्जुन को साथ लेकर घूम रहे थे। मार्ग में उन्हें एक निर्धन ब्राह्मण मिला जो सूखी घास खा रहा था, पर उसकी कमर में तलवार लटक रही थी। अर्जुन ने कारण पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि वह अपने कुछ ‘शत्रुओं’ को दंड देना चाहता है। जब अर्जुन ने पूछा कि वे कौन हैं, तो ब्राह्मण ने कहा पहला नारद, जो निरंतर भजन करके प्रभु को विश्राम नहीं लेने देते; दूसरी द्रौपदी, जिसने भगवान को भोजन बीच में छोड़कर बुला लिया; उन्हें पांडवों को दुर्वास ऋषि के शाप से बचाने जाना पड़ा। तीसरी शबरी, जिसने उन्हें जूटे फल खिलाए; चौथा प्रह्लाद, जिसने उन्हें कष्ट सहने पर विवश किया और पांचवां स्वयं अर्जुन, जिसने भगवान को अपना सारथी बना दिया। कितना कष्ट हुआ होगा मेरे प्रभु को। यह कहते ही ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। यह देख अर्जुन का घमंड चूर-चूर हो गया। उसने श्रीकृष्ण से क्षमा मांगते हुए कहा मान गया प्रभु, इस संसार में न जाने आपके कितने तरह के भक्त हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ।

महत्त्वपूर्ण

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kannami Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006. Editor : Bhupendra Kumar (Responsible for selection of news under PRB Act.) Group Editor - Shreekant Parashar. Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.Regn No.RNI No. : TNMH / 2013 / 52520

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वार्तािक, टेंडर एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी यह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पुरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकाने को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बर्ना सकता। – दक्षिण भारत राष्ट्रमत

सामयिक

गाजा में एक नई सुबह : युद्ध से शांति की ओर कदम

गाजा, जो दशकों से संघर्ष और विनाश की मार झेलता आ रहा है, आज एक बार फिर उम्मीद की दहलीज पर खड़ा है। युद्ध विराम लागू होने के बाद वहां के लोगों के चेहरों पर पहली बार भय के बजाय राहत की झलक दिखी है। यह छोट-सा भूभाग, जो लंबे समय से बारूद की गंध और मलबे के बीच सांस ले रहा था, अब धीरे-धीरे जीवन के रंगों की ओर लौटने की कोशिश कर रहा है। यह वापसी केवल शांति की नहीं, बल्कि उस मानवीय अस्तित्व की है जो हिंसा की आग में झुलस गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुए 20-सूत्रीय शांति प्रस्ताव ने एक नया इतिहास रचा। हमारा और इजराइल के बीच वर्षों के स्तब्धजित संघर्ष के बाद आखिरकार एक अस्थायी संघर्षविराम पर सहमति बनी। इस समझौते के तहत हमारा ने सभी जीवित इजरायली बंधकों को अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस की मदद से रिहा किया, जबकि इजरायल ने लगभग दो हजार फिलिस्तीनी कैदियों को आजादी दी। इसी के साथ बमबारी रुक गई, और राहत सामग्री से भरे ट्रक गाजा में विवेश करने लगे। यह क्षण लोगों के लिए किसी पुनर्जन्म जैसा था-पहली बार आसमान से गिरती आग की जगह वहां राहत के बादल उमड़े। युद्ध विराम के बाद गाजा की गलियों में जो बदलाव दिख रहा है, वह केवल भौतिक नहीं, भावनात्मक भी है। जहां कल तक हर घर में मातम था, आज वहां बच्चे फिर से खेल के मैदानों की ओर लौट रहे हैं। अस्पतालों में घायलों का इलाज चल रहा है, स्कूलों में किताबों की सरसराहट सुनाई दे रही है, और बाजारों में खरीद-फरोख्त की हलचल ने जीवन की वापसी का संकेत दिया है। परंतु इन हलचलों के पीछे अभी भी वह डर, वह अविश्वास और वह गहरी पीड़ा मौजूद है जो वर्षों के संघर्ष ने लोगों के मन में छोड़ दी है। समझौते

की शर्तों के अनुसार अब गाजा का प्रशासन एक अंतरिम फिलिस्तीनी तकनीकी समिति को सौंपा जाना है, जो आगे चलकर फिलिस्तीनी अथॉरिटी को सत्ता हस्तांतरित करेगी। यह कदम नाजुक और जटिल है, क्योंकि इजरायल ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी की सीधी भूमिका को लेकर आपत्ति जताई है। दूसरी ओर हमारा को किसी भी राजनीतिक या प्रशासनिक भूमिका से बाहर रखा गया है, हालांकि संगठन अपने अस्तित्व और हथियार छोड़ने को लेकर अभी भी असमंजस में है। इस स्थिति ने गाजा के शासन तंत्र को एक कठिन मोड़ पर ला खड़ा किया है, जहां शांति और शक्ति संतुलन दोनों को बनाए रखना एक चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती है गाजा का पूर्ण निरस्त्रीकरण। ट्रंप की योजना के अनुसार क्षेत्र को सैन्य प्रभाव से मुक्त कर नागरिक शासन की स्थापना करनी है। मगर हमारा का तर्क है कि जब तक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य का औपचारिक गठन नहीं होता, वह अपने हथियार नहीं छोड़ेगा। इजरायली सेना अभी भी गाजा के लगभग आधे से अधिक हिस्से पर सुरक्षा घेरे में मौजूद है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह संघर्षविराम स्थायी शांति में बदल पाएगा, या यह केवल एक अस्थायी विराम है, जिसके पीछे फिर कोई नई आग सुलग रही है। फिर भी, जो सबसे सकारात्मक पहलु उभरकर सामने आया है, वह है मानवीय राहत और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने एकजुट होकर गाजा को फिर से खड़ा करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। संयुक्त राष्ट्र, मित्र, क्तर और तुर्क जैसे देशों ने आर्थिक सहायता और राहत सामग्री भेजनी शुरू कर दी है। अस्पतालों में नई दवाएं पहुंच रही हैं, पानी और बिजली की आपूर्ति धीरे-धीरे बहाल हो रही है, और अस्थायी शिविरों में रहने वाले हजारों शरणार्थी अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं। फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई ने कई परिवारों को पुनर्मिलन की भावनात्मक राहत दी है। हालांकि, अभी भी कई परिवार अपने लापता प्रियजनों के बारे में अनिश्चित हैं। मृतकों के शवों की खोज और पहचान को लेकर विवाद जारी है, जिससे इस राहत प्रक्रिया में भावनात्मक तनाव बना हुआ है। लेकिन फिर भी, इन सबके बीच एक विश्वास की डोर बंधी है-कि अब गाजा के लोग शायद एक नए सवेरा की ओर बढ़ रहे हैं। गाजा के भविष्य को लेकर दो मुख्य मुद्दे अभी भी चर्चा में हैं-पहला, इजरायली सेना की पूर्ण वापसी और दूसरा, दीर्घकालिक सुरक्षा व्यवस्था की रूपरेखा। अंतरराष्ट्रीय बोर्ड, जिसकी अध्यक्षता ट्रंप कर रहे हैं, अब पुनर्निर्माण और प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय हो गया है। फिलिस्तीनियों को आवागमन, रोजगार और शिक्षा की स्वतंत्रता देने की दिशा में भी कुछ शुरुआती कदम उठाए गए हैं। इन पहलियों के बीच गाजा में एक नया भरोसा जन्म ले रहा है, हालांकि यह

भरोसा बहुत नाजुक है। शांति की यह प्रक्रिया आसान नहीं है। युद्ध ने वहां की सामाजिक संरचना, अर्थव्यवस्था और मनोविज्ञान-तीनों को गहराई से झकझोर दिया है। हजारों बच्चे जिन्होंने अपने माता-पिता को खोया, या जिन्होंने बमों के बीच बचपन बिताया, उनके लिए यह बदलाव केवल भौतिक नहीं, मानसिक उपचार की शुरुआत है। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां अब मनोवैज्ञानिक परामर्श और शिक्षा बहाली के कार्यक्रम चला रही हैं, ताकि नई पीढ़ी युद्ध की छाया से बाहर आ सके। पर यह भी सच है कि अभी स्थायी समाधान की राह में कई बाधाएं बाकी हैं। हमारा का हथियारबंद ढांचा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, इजरायली सेना की सीमित मौजूदगी अभी भी फिलिस्तीनी स्वायत्तता पर सवाल उठाती है, और फिलिस्तीनी अथॉरिटी की प्रशासनिक क्षमता भी परखी जा रही है। ऐसे में शांति और स्थिरता की राह केवल समझौतों या मध्यस्थताओं से नहीं, बल्कि आपसी विश्वास और न्याय की पुनर्स्थापना से तय होगी।

गाजा के लोग अब यह समझ चुके हैं कि स्थायी शांति केवल हथियार डालने से नहीं, बल्कि जीवन को फिर से अर्थ देने से आती है। वे जानते हैं कि रोटी, शिक्षा और सम्मान-इन तीनों के बिना कोई भी शांति टिक नहीं सकती। यही कारण है कि आज गाजा में स्कूलों के खुलने, बाजारों के सजने और घरों में दीये जलने की खबरें किसी राजनीतिक घटना से अधिक मानवीय विजय का प्रतीक बन गई हैं। इस युद्ध विराम ने वहां के आम जनजीवन को न केवल राहत दी है, बल्कि यह साबित किया है कि सबसे अंधेरी रात के बाद भी सवेरा संभव है। अब यह सवेरा कितनी देर तक ठहरता है, यह आने वाले समय की कसौटी पर निर्भर करेगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि गाजा की यह नई शुरुआत केवल युद्ध का समाप्ति नहीं, बल्कि न्याय, मानवता और स्थायित्व की ओर पहला कदम है। और शायद यही वह राह है, जिस पर चलते हुए आने वाली पीढ़ियां एक दिन सच संकेती-गाजा ने अंततः जीवन को जीत लिया।

मंथन

दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता के उपाय

स्थिति इसलिए भी बनी, क्योंकि कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार की गलत नीतियों के चलते किसान को खाद्य वस्तुओं की बजाय, ईंधन, प्लास्टिक और फूलों की फसल उगाने के लिए, कुछ विभाग ने जागरूकता के अभियान चलाए। यही वजह रही कि भूमंडलीकरण के दौर में दालों की पैदावार लगातार कम होती चली गई। दाल उत्पादन का रकबा लगभग 15 हजार हेक्टेयर कम हो गया। भारत में दालों की सालाना खपत 220 से 230 लाख टन है। मांग और आपूर्ति के इस बड़े अंतर के चलते जमाखोरों और दाल के आयातक व्यापारियों को भी बारे-न्यारे करने का मौका मिल जाता है।

पौष्टिक आहार देश के हरेक नागरिक के स्वास्थ्य जीवन से जुड़ा अहम प्रश्न है। संविधान के मूलभूत अधिकारों में भोजन का अधिकार शामिल है। चूंकि दालें प्रोटीन और पौष्टिकता का महत्वपूर्ण जरिया हैं। चूंकि दालें आयात करनी होती हैं, इसलिए इनके भाव भी बीच-बीच में बढ़ जाते हैं। इस कारण मध्यवर्गीय व्यक्ति की थाली से दाल गायब होने लगती है। चुनावों दाल व्यक्ति की सेहत से जुड़ी हैं और बीमारी की हावात में तो रोगी को केवल दाल-रोटी खाने की ही सलाह चिकित्सक देते हैं। वर्ष 1951 में प्रतिव्यक्ति दालों की उपलब्धता 60 ग्राम थी,जो वर्ष 2010 में घटकर 34 ग्राम रह गई। जबकि अंतरराष्ट्रीय मानकों के

अनुसार यह मात्रा 80 ग्राम होनी चाहिए। दालें भारत में प्रोटीन का प्रमुख स्रोत मानी जाती हैं। लेकिन स्थानीय मांग पूरी करने के लिए दाल उत्पादन में किसान को बड़ी मशकत करनी पड़ती है। तुअर दाल की फसल आठ माह में तैयार होती है। बावजूद किसान को उचित दाम नहीं मिलते हैं। गोया,किसान साल में एक फसल उगाने में रुचि कैसे लें? विदेशों में रहने वाले भारतीय भी सबसे ज्यादा तुअर की दाल खाना पसंद करते हैं। देश में सबसे अधिक चने और अरहर की खेती होती है। इनके अलावा मूंग और उड़द की दालें पैदा होती हैं। देश में 10 राज्यों के किसान दालों की खेती करते हैं। इन्में सबसे अधिक उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। दालें मुख्य रूप से खरीफ की फसल हैं,जो वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं। इस ऋतु में करीब 70 प्रतिशत किसान को उत्पादन होता है।

केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार दालों के तात्कालिक भाव 85.42 प्रति किलो से लेकर 112.88 रुपए किलो तक हैं। भावों में इस उछाल का कारण जमाखोरी और सड़ेंबाजी के साथ आयात का कुचक्र है। टाटा, मंहिद्रा, ईंजी-सेठ से जुड़ी हैं और रिलाइंस जैसे बड़ी कंपनियां जब से दाल के व्यापार से जुड़ी हैं,तब से ये जब चाहे तब मुनाफे के लिए दाल से खिलवाड़ करने लग जाती हैं। जब कंपनियां बड़ी तादाद में दालों का भंडारण कर लेती हैं,तो भावों में कृत्रिम उछाल आ जाता है। हालांकि

केंद्र सरकार ने दालों का भंडारण सितंबर 2024 से सीमित किया हुआ है। इस नाते यह कहने में कोई दो राय नहीं कि विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बात तो छोड़िए, देशी कंपनियों भी भारतीय कृषि को बदहाल बनाए रखना चाहती हैं। आयात की जब इन्हें खुली छूट मिल जाती है तो ये जरूरत से ज्यादा दाल व तेल का आयात करके भारत को डंपिंग ग्राउंड बना देती हैं। तय है, कालांतर में भारत की तरह दूसरे देशों में यदि मौसम रूठ जाता है तो दाल और प्याज की तरह खाद्य-तेल के भाव भी आसमान छूने लग जाते हैं। सरस्ते तेल का आयात जारी रहने की वजह से ही भारत में तिलहन का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। बावजूद हमारे नेता ऐसी नीतियों को बढ़ावा देने की कोशिशों में लगे रहे हैं कि दलहन और तिलहत के क्षेत्र में भारत पूरी तरह परावलंबी बना रहे। इस परिस्थि में मनमोहन सरकार के कृषि मंत्री बलराम जाखड़ ने सलाह दी थी कि भारत अफ्रीका में दालें उगाए और फिर आयात करे। इसी तरह संगम सरकार में कृषि मंत्री रहे शरद पवार म्यांमार और उरुग्वे में दालें पैदा करकर आयात करना चाहते थे। ये सुझाव समझ से परे हैं। आखिर ऐसे क्या रहस्य हैं कि हमारे नीति-नियंता विदेशी धरती पर तो दाल उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, किंतु देश के किसानों को लाभकारी मूल्य देना नहीं चाहते ? ऐसी मंशाएं देश की खाद्य सुरक्षा को जहां-बूझकर संकट में डालने जैसी लगती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नाते 100 पिछड़े जिलों में दालों के उत्पादन का दायरा बढ़ाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है।

नजरिया

मारिया की राजनीति और राहुल गांधी की सियासी उलझन

समर्थन, इजराइल की नीतियों की पक्षधरता और आर्थिक निजीकरण की वकालत शामिल है- ने कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए परोपेश वाली स्थिति पैदा कर दी है।

मारिया कोरिना माचाडो का राजनीतिक उदय वेनेजुएला की समाजवादी सरकारों के खिलाफ प्रतिरोध पर आधारित है। 1967 में जन्मी माचाडो, एक पूर्व सांसद और इंजीनियर, 2012 से विपक्षी गठबंधन की प्रमुख रही हैं। उन्होंने हूगो चावेज और निकोलास मादुरो की सरकारों पर चुनावी धांधली, भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोप लगाए। ऐसा ही राहुल गांधी भारत में भाजपा सरकार के खिलाफ करते हैं। 2024 के राष्ट्रपति चुनावों में, मादुरो सरकार ने मारिया को अयोग्य घोषित कर दिया, जिसके बाद उन्होंने एडुअर्दो गोजालेज को समर्थन देकर विपक्ष को एकजुट किया। इन प्रयासों ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिलाई, जिसमें अमेरिकी प्रतिबंधों और विदेशी सहायता की मांग शामिल थी। मारिया की विचारधारा की अपनी राजनीति है। उन्होंने अपना पुरस्कार ट्रम्प को समर्पित करते हुए उन्हें हमारे संघर्ष का निर्णायक समर्थक बताया। मारिया ने अपने देश में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप की भी वकालत की, जिससे वेनेजुएला में आर्थिक संकट बढ़ा। इजराइल के प्रति उनका रुख साफ है। उन्होंने इजराइल को स्वतंत्रता का 'सच्चा सहयोगी' कहा और गाजा संघर्ष में इजराइली कार्रवाइयों का समर्थन किया। इसके अलावा, माचाडो राज्य तेल कंपनी पीडीवीएसए के निजीकरण की भी पक्षधर हैं, जो समाजवादी विचारधारा के विपरीत है।

इस बीच मारिया को नोबेल की घोषणा होते ही भारत में कांग्रेस ने मारिया के पुरस्कार को अपने राजनीतिक नैरेटिव से जोड़ने का प्रयास किया। कांग्रेस नेता राशिद अह्वी ने कहा कि मारिया ने वेनेजुएला में

समर्थन, इजराइल की नीतियों की पक्षधरता और आर्थिक निजीकरण की वकालत शामिल है- ने कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए परोपेश वाली स्थिति पैदा कर दी है।

मारिया कोरिना माचाडो का राजनीतिक उदय वेनेजुएला की समाजवादी सरकारों के खिलाफ प्रतिरोध पर आधारित है। 1967 में जन्मी माचाडो, एक पूर्व सांसद और इंजीनियर, 2012 से विपक्षी गठबंधन की प्रमुख रही हैं। उन्होंने हूगो चावेज और निकोलास मादुरो की सरकारों पर चुनावी धांधली, भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोप लगाए। ऐसा ही राहुल गांधी भारत में भाजपा सरकार के खिलाफ करते हैं। 2024 के राष्ट्रपति चुनावों में, मादुरो सरकार ने मारिया को अयोग्य घोषित कर दिया, जिसके बाद उन्होंने एडुअर्दो गोजालेज को समर्थन देकर विपक्ष को एकजुट किया। इन प्रयासों ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिलाई, जिसमें अमेरिकी प्रतिबंधों और विदेशी सहायता की मांग शामिल थी। मारिया की विचारधारा की अपनी राजनीति है। उन्होंने अपना पुरस्कार ट्रम्प को समर्पित करते हुए उन्हें हमारे संघर्ष का निर्णायक समर्थक बताया। मारिया ने अपने देश में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप की भी वकालत की, जिससे वेनेजुएला में आर्थिक संकट बढ़ा। इजराइल के प्रति उनका रुख साफ है। उन्होंने इजराइल को स्वतंत्रता का 'सच्चा सहयोगी' कहा और गाजा संघर्ष में इजराइली कार्रवाइयों का समर्थन किया। इसके अलावा, माचाडो राज्य तेल कंपनी पीडीवीएसए के निजीकरण की भी पक्षधर हैं, जो समाजवादी विचारधारा के विपरीत है।

इस बीच मारिया को नोबेल की घोषणा होते ही भारत में कांग्रेस ने मारिया के पुरस्कार को अपने राजनीतिक नैरेटिव से जोड़ने का प्रयास किया। कांग्रेस नेता राशिद अह्वी ने कहा कि मारिया ने वेनेजुएला में

और साम्राज्यवाद-विरोध पर टिकी है। पार्टी ने फिलिस्तीन मुद्दे पर हमेशा समर्थन दिया, जो उसके मुस्लिम मतदाता आधार और वामपंथी सहयोगियों से जुड़ा है। मारिया का इजराइल-समर्थक रुख कांग्रेस की नीतियों से सीधा टकराव पैदा करता है। कांग्रेस ने गाजा हमलों की निंदा की है, जबकि मारिया ने इजराइल को 'स्वतंत्रता का सहयोगी' बताया। इसी प्रकार, माचाडो का ट्रम्प समर्थन कांग्रेस के लिए असहज है, जिसने भाजपा पर 'ट्रम्प-मोदी गठजोड़' के आरोप लगाए हैं। माचाडो की निजीकरण नीति भी कांग्रेस की समाजवादी नीति के विपरीत है। विश्लेषणात्मक रूप से, ये अंतर्विरोध कांग्रेस की वैचारिकता को चुनौती देते हैं। यदि कांग्रेस मारिया का समर्थन जारी रखती है, तो यह उसके वोट बैंक और सहयोगी दलों में दरार डाल सकती है, विशेष रूप से मुस्लिम और वामपंथी समूहों में, जहां माचाडो को इजराइल-समर्थक माना जाता है।यदि पार्टी माचाडो का समर्थन करती है, तो वह वैचारिक समझौता करेगी, जिससे वोट बैंक दरक सकता है-उदाहरण के लिए, 2024 चुनावों में मुस्लिम वोटों का करीब 70 प्रतिशत कांग्रेस को मिला था। यदि मौन साधती है या असलोचना करती है, तो भाजपा इसे लोकतंत्र-विरोधी' बताकर प्रचार करेगी। राहुल गांधी की व्यक्तिगत स्थिति और भी जटिल है; वे न तो पूर्ण समर्थन कर पा रहे हैं और न विरोध। यह गहन दुविधा,जटिल उलझन कांग्रेस की राजनीतिक कमजोरी को उजागर करती है। राजनीतिक विश्लेषण की दृष्टि से उनके मारिया कोरिना माचाडो का नोबेल पुरस्कार उनके मुद्दों पर मुखर दिखाया जाता है। विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखें तो यह नैरेटिव बहुत सटीक है और राहुल तथा मारिया के बीच वैचारिक विरोधाभासों को अन्वेषण करता है। कांग्रेस की ऐतिहासिक विचारधारा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता

महत्त्वपूर्ण

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kannami Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006. Editor : Bhupendra Kumar (Responsible for selection of news under PRB Act.) Group Editor - Shreekant Parashar. Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.Regn No.RNI No. : TNMH / 2013 / 52520

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वार्तािक, टेंडर एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी यह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पुरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकाने को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बर्ना सकता। – दक्षिण भारत राष्ट्रमत

